

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1973/श्रावण 9, 1895

No. 181]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1973/SRAVANA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1973

**G.S.R. 368(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Seventh Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the said Regulations, under "Madhya Pradesh", for the entry:—

"Secretaries to Government—8"

the following entries shall be substituted, namely:—

"Principal Secretary to Government

.. 1"

"Secretaries to Government

.. 7"

[No. 33/9/71-AIS(II)-A.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

**मंत्रिमण्डल सचिवालय**  
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)  
**अभिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1973

सा० का० नि० 368 (अ०)—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सान्ना संशोधन विनियम, 1973 कहा जा सकेगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. उक्त विनियमों की अनुसूची में, “मध्य प्रदेश” के अधीन,  
“सरकार के सचिव...8”

प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

“सरकार के प्रधान सचिव...1”

“सरकार के सचिव...7”

[स० 33/9/71-अ० भा० से० (II)-क]

श्रवण कुमार,  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।